

Shri Alagesan: We are having this matter under consideration, but it was decided that as soon as we are in a position to take up the manufacture of certain products, then it will be time for this corporation to be formed.

Shri Vasudevan Nair: The hon. Minister says that they are trying to have some collaboration. May I know whether the Government itself has gone into some independent investigation of the possibilities of the units that we can start and, if so, in which places?

Shri Alagesan: We are having a cell and that cell is doing very valuable work, and is analysing the possibilities as to what we should produce and how we should proceed about it. We are also having an independent assessment, but in this very highly technical field, we are bound to take the assistance and advice of others.

Shri P. C. Borooah: May I know whether the Board of Directors that is proposed in respect of this corporation will consist of members like other public sector corporations, nominated by the Government who will have no stake in the corporation, and also whether the Government has under contemplation the setting up of any machinery just to check the working of the Board itself?

Shri Alagesan: It is wrong to say that the members of the Board will not have any stake; they will not be private shareholders, but they owe a responsibility to Government and they are expected to discharge their duties faithfully.

Dr. Ranen Sen: Is there any contemplation to have foreign collaboration in connection with this corporation and, if so, what are the foreign companies that are contacted in this regard?

Shri Alagesan: There is a consortium of American companies who have come forward to collaborate

with us and we are going to have talks with them.

Shri Oza: May I know whether there will be only one corporation or some regional corporations or subsidiary corporations? What is the thinking of the Government in this matter?

Shri Alagesan: To begin with, the main task of the corporation will be with regard to the petro-chemical units that we propose to set up in Gujarat in connection with the refinery that will be commissioned there shortly; it will be first seized of that, and if our activities expand, it will be time for the corporation to consider other matters.

Shri P. Venkatasubbaiah: While formulating the fourth Plan outlay for petro-chemical industries in this country, I would like to know whether the capital outlay of this Corporation will also be taken into consideration and, if that is so, what is the position?

Shri Alagesan: In consultation with this Ministry, mainly, the Planning Commission has taken steps to provide money for this; it has made allocations.

डाक द्वारा विश्वविद्यालय की शिक्षा

श्री:

* 771. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन विश्वविद्यालयों ने प्रयोगात्मक आधार पर डाक द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था प्रारम्भ की है तथा उसमें उन्हें कितनी सफलता मिली है ;

(ख) डाक द्वारा शिक्षा देने के कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) कितने लोगों ने इस शिक्षा व्यवस्था में दाखिला लिया है और उनमें से कितने प्रतिशत व्यक्ति परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं और उनकी पढ़ाई का स्तर कैसा है ; और

(घ) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति वर्ष कितना खर्च करना पड़ता है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त बर्दान) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) केवल दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1962-63 शैक्षिक वर्ष से शुरू होने वाली पाइलेट योजना के रूप में बी०ए० (पास) उपाधि के लिए पत्रव्यवहार पाठ्यक्रम की स्थापना की है । हालांकि पत्र व्यवहार पाठ्यक्रम को विद्यार्थी समुदाय द्वारा उत्तरोत्तर लोकप्रियता प्राप्त हुई है, योजना की सफलता का किसी भी प्रकार का वास्तविक मूल्यांकन तभी संभव होगा जब इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद, सितम्बर 1962 में पत्रव्यवहार पाठ्यक्रम में नामांकन कराने वाले विद्यार्थियों का दल नवम्बर, 1965 के भन्त तक प्रेजुएट बनेगा ।

(ख) चौथा पंचवर्षीय आयोजना के संदर्भ में, विभिन्न स्तरों पर पत्रव्यवहार पाठ्यक्रम के कार्यक्रम के विकास के लिए निम्नलिखित योजनायें विचाराधीन हैं :—

1. क्षेत्रीय आधार पर चुने गये तीन या चार विश्वविद्यालयों में कला में पूर्व-स्नातक (ग्रण्डर प्रेजुएट) स्तर

पर पत्र व्यवहार पाठ्यक्रम की योजना का विस्तार ;

2. दिल्ली विश्वविद्यालय में कला में स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) उपाधि तथा बी०एस०सी० (पास) उपाधि के लिए पत्रव्यवहार पाठ्यक्रम की शुरुआत ;

3. बड़ोदा तथा मैसूर विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली तथा पूर्वी क्षेत्र में एक अन्य केन्द्र में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम शुरू करना ; और

4. डिप्लोमा तथा डिग्री दोनों स्तरों पर, प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरी में एक विस्तृत योजना तैयार करने के लिए, चार क्षेत्रीय केन्द्रों तथा क्षेत्रीय एजेंसियों के साथ, एक केन्द्रीय पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम व्यूरो की स्थापना ।

(ग) पत्रव्यवहार पाठ्यक्रम के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के बी०ए० (पास) उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या
1962-63.	1112
1963-64.	1410
1964-65.	1929
1965-66.	2600

यह आशा की जाती है कि पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के पढ़ने दल के परीक्षा परिणाम नवम्बर, 1965 तक घोषित हो जायेंगे ।

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्र-व्यवहार द्वारा बी०ए० (पास) उपाधि

पाठ्यक्रम में एक विद्यार्थी के लगभग 200/- रुपए वार्षिक खर्च होने है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो जापन सदन पटल पर रखा गया है उसमें बतलाया गया है कि मन् 1962 से 1966 तक के कारेमपान्डेम कोर्स में छात्रों की संख्या 2600 है । मैं जानना चाहता हूँ कि कितने छात्रों ने अन्तिम वर्ष में प्रार्थनापत्र भेजे थे, और 2600 ही विद्यार्थी क्यों भरती हुए, और इस स्कीम को भागे बढ़ाने के लिए क्यों प्रयत्न नहीं किया गया ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जहां तक इस योजना को भागे बढ़ाने का प्रश्न है उसका विवरण तो दिया जा चुका है । अब अन्तिम रूप से जब—

श्री म० ला० द्विवेदी : छात्रों के बारे में ।

श्री भक्त दर्शन : छात्रों के बारे में विवरण में बताया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : जो बताया जा चुका है उसे बताने की जरूरत नहीं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : उसमें नहीं बताया गया है । इसमें 2600 विद्यार्थी बतलाए गए हैं । अर्जी देने वाले दस हजार विद्यार्थी थे । मैं जानना चाहता था कि उनमें से 2600 ही क्यों भरती किए गए ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इसका कारण तो स्पष्ट है कि हमारे पास योग्य अध्यापकों की कमी है इसलिए हम सीमित संख्या में ही विद्यार्थियों को इसमें स्थान दे सके हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : जहां तक मेरा स्थान है, शिक्षा मंत्रालय ने यह विज्ञापित किया था कि दिल्ली के अलावा अन्य विश्वविद्यालय हैं, जैसे शान्ति निकेतन

आदि, जहां डाक से चलने वाला पाठ्यक्रम चालू किया जाएगा । इन के चालू न करने का क्या कारण है ? इस वक्तव्य में यह बतलाया गया है कि कुछ रोजनल लेवल पर ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे जहां पर डाक से चलने वाला पाठ्यक्रम चालू किया जाएगा । मैं जानना चाहता हूँ कि वे कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं !

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, अभी यह अन्तिम रूप से तै नहीं हुआ है कि किन नए विश्वविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम को शुरू किया जाएगा । जैसा कि विवरण में दिया गया है चौथी योजना में तीन चार विश्वविद्यालयों में इसे शुरू किया जाएगा । जहां तक विश्वभारती का सम्बन्ध है, अभी इस पर विचार नहीं किया जा सका है क्योंकि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि अभी चौथी योजना पर अन्तिम रूप से विचार नहीं किया गया है । जब अन्तिम रूप से विचार कर लिया जाएगा तभी इस प्रश्न पर विचार होगा और तभी कार्रवाई भागे बढ़ायी जा सकेगी ।

Shri S. C. Samanta: The statement says that B.Sc. course will also be opened. May I know how the practical experiments will be shown to the students?

Shri Bhakt Darshan: The whole matter is under examination.

Shri D. C. Sharma: May I know what steps the government is taking in order that the dilution of academic standards in these correspondence courses does not take place?

Shri Bhakt Darshan: I must assure the hon. member that instead of dilution of the standards, we have been able to raise the standard.

Shri Kapur Singh: The form of his question is grammatically wrong, Sir.

Shri D. C. Sharma: The Minister has made a general statement. I wanted to know what steps are being taken. . .

Mr. Speaker: One hon. member objected that his question was grammatically wrong.

Shri D. C. Sharma: Who said that, Sir?

Shri Kapur Singh: The hon. member said "something, something . . . in order that" etc. He should have said "in order to".

Shri D. C. Sharma: He is entirely wrong. His English is Punjabi English. I take strong exception to this kind of thing.

Mr. Speaker: I cannot decide because I confess the superiority of both to me.

Shri D. C. Sharma: I want that this should be referred to some authority on English. He knows only Punjabi-English.

श्री राम सहाय पाण्डेय : पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम की पायलट योजना के रूप में यह जो कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, उस को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वे कौन से विश्वविद्यालय हैं, जिन्होंने इस योजना को स्वीकार कर के पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम का कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस विवरण में यह बताया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को दो सौ रुपये प्रति-वर्ष व्यय करना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस खर्च में कोई कमी करने की व्यवस्था की गई है।

श्री भक्त दर्शन : जैसा कि विवरण में बताया गया है, अभी तक केवल एक ही विश्वविद्यालय, अर्थात् दिल्ली, में यह पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। आगे के लिए अवश्य विचार किया जा रहा है। जहाँ तक खर्च घटाने का सम्बन्ध है,

मैं सदस्य महोदय को भावनात्मक बना चाहता हूँ कि खर्च को जितना घटाया जा सकता था या कम से कम रखा जा सकता था, वह किया गया है।

श्री बहापाल सिंह : सरकार के ध्यान में यह बात तो है कि इस योजना से एड्जुकेशन का स्टैंडर्ड गिरेगा। तो क्या सरकार ने यह तय किया है कि इस योजना के अन्तर्गत किसी भी परीक्षार्थी को ऊंची डिविजन न दे कर केवल बर्द डिविजन दी जाये ?

श्री भक्त दर्शन : मैं माननीय सदस्य से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि इस की वजह से शिक्षा का स्तर गिरा है। हमारी सूचना के मुताबिक इस से स्तर ऊंचा हुआ है। अध्ययन का कार्यक्रम भी सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है।

Shri Daji: Has the Government considered this aspect of the matter that there are a large number of working youths who should be given an opportunity for higher studies; if so, may I know whether in the Fourth Five Year Plan adequate arrangements will be made throughout the country by way of correspondence course or some other course so that those who are working may also be able to get higher education?

Shri Bhakt Darshan: I am thankful to the hon. Member for giving support to the scheme. As I have already explained in the statement, in the context of the Fourth Five Year Plan, extension of the scheme of correspondence courses at undergraduate level in Arts to 3 or 4 more universities selected on a regional basis is under consideration.

Shri Daji: Why only to three or four universities, why is it not being done throughout the country so that education may be available to the working youth?

Shri Bhakt Darshan: If we could, we would have gladly done so. But financial considerations also come in the way. Let us start with three or four universities.

नये विश्वविद्यालय

* 772. $\left. \begin{array}{l} \text{श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :} \\ \text{श्री प्रकाशवीर शास्त्री :} \end{array} \right\}$

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले वर्ष कुछ नये विश्वविद्यालय खोलने के लिए अनुमति प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो ये विश्वविद्यालय किन किन राज्यों में खोले जायेंगे ; और

(ग) क्या आयोग कुछ और नये विश्वविद्यालय खोलने के प्रश्न पर भी विचार कर रहा है और उन के बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). विवरण तमा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राजी हो गया है :—

1. मयुराई (मद्रास राज्य)
2. कानपुर तथा मेरठ (उत्तर प्रदेश)
3. सूरत और भावनगर (गुजरात)
4. पाण्डिचेरी
5. कोच्चा

6. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली ।

7. आन्ध्र प्रदेश में एक नया समबद्धित विश्वविद्यालय ।

उपर्युक्त विश्वविद्यालयों में से, चौपी आयोजना-अवधि के दौरान पाण्डिचेरी तथा गोष्ठा में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आयोग सहमत हो गया है ।

प्रत्येक नये विश्वविद्यालय के संस्थापन के साथ यह निर्णय करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए अथवा नहीं और यदि किया जाना चाहिए तो कब । गोष्ठा प्रशासन ने निर्णय किया है कि वहां कुछ कालेजों के संस्थापन के बाद प्रस्तावित विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ।

(ग) आयोग को दो और प्रस्ताव विचारार्थ प्राप्त हुए हैं—एक उत्तर प्रदेश सरकार से—नेनीताल में विश्वविद्यालय के लिए और दूसरा हिमाचल प्रदेश प्रशासन से उसी संघ राज्य क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या इस आयोग ने अनुमति प्रदान करने से पूर्व कोई ऐसे नये विज्ञानों की छांट कर ली है, जो कि इन विश्वविद्यालयों में चालू किये जा सकें ?

श्री भक्त दर्शन : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का समाप्ति नहीं हूँ ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या अनुमति देने से पहले शिक्षा आयोग ने इस प्रकार के नये विज्ञानों का क्षेत्र बूझ लिया है, जिन का पाठ्यक्रम नये खोले जाये वाले विश्वविद्यालयों में चालू किया जा सके ?